captive consumption in power generation is under consideration of the Government in the Ministry of Coal. After the proposal is approved by the Government, appropriate amendment to relevant Acts/Rules will be carried out for the purpose. Exploitation of lignite reserves in Jayamkondom area for captive power generation in the private sector could be considered only after relveant Acts/Rules are amended suitably.

Shortfall in the production of coal

3838. SHRI V. NARAYANASAMY : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Coal India Limited production of coal in the financial year 1991-92 has been far below the target ;

(b) if so, what are the main reasons therefor ; and

(c) what steps Government are taking to increase the production of coal ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA) : (a) No Sir. The production of coal in Coal India Limited during 1991-92 (April 91-Feb. 92) was 180.21 million tonnes against target of 180.17 million tonnes.

(b) and (c) Do not arise.

कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली फिजूलखर्ची को रोका जाना

3839. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने अधिकारियों द्वारा की जाने वाली फिजूलखर्ची को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इन निर्देशों के परिणामस्वरूप कितनी बचत होने की संभावना है ; और

(ग) निर्देशों को सही ढंग से लागू किए जाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० बी० नक्सेगौड़ा) : (क) से (ग) जी, हां। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनियों को प्रशासनिक व्यय जैसे कि समयोपरि भत्ता, यात्रा, दूरभाष, प्रचार, लेखन-सामग्री, स्टाफकार, आदि को न्यूनतम करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके फलस्वरूप कोल इंडिया लि० में 10.41 करोड़ रुपए की बचत की जा सकी है।

सभी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों को उक्त निर्देशों को नियमित रूप से कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बन्द किया जाना

3840. **श्री चतुरानन मिश्र** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद, जिसमें कोयला प्रबन्धन और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, एक स्वायत संस्थान है, जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के खनन क्षेत्रों के लिए जल सप्लाई, जन स्वास्थ्य, सफाई, पर्यावरण नियंत्रण और सामुदायिक विकास कार्यों की देखभाल करता है और यह अंग्रेजों के समय से ही कार्य कर रहा है ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा दी गई सेवाओं के लिए कोयला प्रबन्धन कब से टन भार उपकर दे रहा है और यह उपकर किन से वसूल किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि कोयला प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा दी गई आवश्यक सेवाओं को बन्द कराने का इच्छुक है ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्राधिकरण की कमाई के एकमात्र स्रोत, टनभार